छत्तीसगढ़

सहकारी समाचार

वर्ष- 22 अंक - 11 सितंबर 2025 प्रथम अंक (पाक्षिक) RNI NO. CHHHIN/2012/45105 पृष्ठ-12 मूल्य 500/- वार्षिक

पीएम मोदी ने किया जीविका निधि साख सहकारी संघ का शुभारम्भ

अब महिलाओं को बैंकों या संस्थानों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी : पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य बिहार की ग्रामीण महिलाओं, विशेषकर जीविका से जुड़ी दीदियों को कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी तरह डिजिटल इस व्यवस्था से महिलाओं को बैंकों या संस्थानों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि उन्हें सीधे मोबाइल फोन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए वित्तीय सहयोग मिल सकेगा। उन्होंने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया और बिहार की माताओं-बहनों को शुभकामनाएँ दीं।

पीएम ने गिनाई केंद्र सरकार की योजनाएं

अपने संबोधन में मोदी ने महिला सशक्तिकरण से जुड़ी केंद्र सरकार की योजनाओं का भी उल्लेख किया, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल, आयुष्मान भारत, मुफ्त राशन योजना, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और बैंक सखी जैसी पहलें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये योजनाएँ महिलाओं के जीवन को आसान बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों द्वारा उनकी दिवंगत माताजी पर की गई टिप्पणी को लेकर गहरी पीड़ा भी व्यक्त की और कहा कि, यह अपमान केवल उनकी मां का नहीं, बल्कि देश की सभी माताओं और बेटियों का अपमान है। उन्होंने बिहार की महिलाओं से आग्रह किया कि वे ऐसी मानसिकता को अस्वीकार करें।

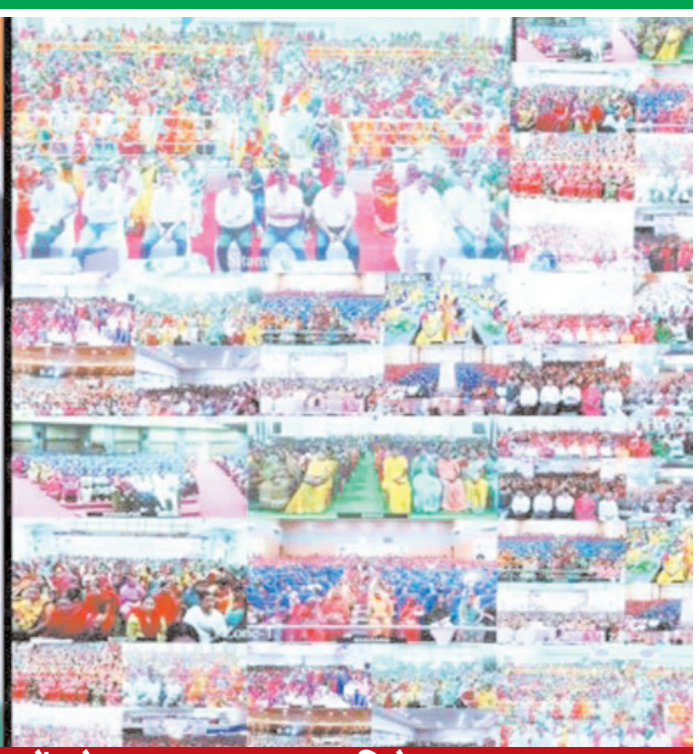

पंजीकृत महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण मिलेगा

इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सहित कई लोग मौजूद रहे। जीविका निधि सहकारी संघ के माध्यम से राज्यभर की पंजीकृत महिला सदस्य अब पारदर्शी और आसान प्रक्रिया से कम ब्याज पर ऋण प्राप्त कर सकेंगी। इस पहल के तहत 12,000 सामुदायिक कार्यकर्ताओं को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्यक्रम से लगभग 20 लाख ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित होंगी।

किसानों के लिए मुख्यमंत्री की बड़ी पहल : इस माह मिलेगा 60 हजार टन अतिरिक्त यूरिया

चालू खरीफ सीजन में अब तक 6.39 लाख टन यूरिया वितरित, गत वर्ष इसी अवधि में हुआ था 6.17 लाख टन का वितरण

■ **राज्य में यूरिया और अन्य रासायनिक खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध, किसानों की मांग पर केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया अतिरिक्त आबंटन**

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर किसानों के हित में एक बड़ी राहत मिल रही है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 60 हजार टन अतिरिक्त यूरिया का आबंटन स्वीकृत किया है। इसमें सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में 20 हजार टन, द्वितीय सप्ताह में 35 हजार टन और शेष 5 हजार टन की आपूर्ति माह के अंत तक सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों की हर आवश्यकता पर राज्य सरकार संवेदनशील है और यह अतिरिक्त आबंटन उनकी खरीफ फसलों को सुरक्षित रखने में सहायक होगा।

मार्कफेड अधिकारियों ने बताया कि चालू खरीफसीजन के लिए 28 अगस्त की स्थिति में सहकारी क्षेत्र में 3 लाख 91 हजार 79 मीट्रिक टन और निजी क्षेत्र में 3 लाख 11 हजार 563 मीट्रिक टन, इस तरह कुल 7 लाख 2 हजार 642 मीट्रिक टन यूरिया का भंडारण किया गया है। इसके विरुद्ध 6 लाख 38 हजार 599 मीट्रिक टन यूरिया किसानों को वितरित किया जा चुका है। इसमें 3 लाख 42 हजार 444 मीट्रिक टन सहकारी क्षेत्र और 2 लाख 96 हजार 155 मीट्रिक टन निजी क्षेत्र से वितरण शामिल है।

2 लाख 91 हजार 59 बॉटल नैनो यूरिया का भंडारण

प्रदेश में किसानों के लिए नैनो खाद की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सहकारी क्षेत्र में 1 लाख 78 हजार 919 और निजी क्षेत्र में 1 लाख 12 हजार 140, इस तरह कुल 2 लाख 91 हजार 59 बॉटल नैनो यूरिया का भंडारण हुआ है। इसी प्रकार सहकारी क्षेत्र में 1 लाख 58 हजार 809 और निजी क्षेत्र में 79 हजार 810, कुल 2 लाख 38 हजार 619 बॉटल नैनो डीएपी संग्रहित किया गया है। अब तक किसानों को 2 लाख 32 हजार 652 बॉटल नैनो यूरिया और 1 लाख 85 हजार 136 बॉटल नैनो डीएपी वितरित किया जा चुका है।

यह आँकड़ा पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 6 लाख 17 हजार 798 मीट्रिक टन वितरण से अधिक है, जो इस बार की बेहतर आपूर्ति व्यवस्था का प्रमाण है।

सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में 15.64 लाख टन खाद का भंडारण

प्रदेश में चालू खरीफ सीजन के लिए भारत सरकार ने 14.62 लाख टन रासायनिक खाद का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके विरुद्ध सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में 15.64 लाख टन का भंडारण कर लिया गया है। भंडारण के आधार पर किसानों को अब तक 13.19 लाख टन खाद वितरित किया गया है। यह व्यवस्था बताती है कि समितियों और निजी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं और किसानों को किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी।

किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है सरकार : सीएम

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि खाद, बीज और सिंचाई जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों से खरीफसीजन में किसानों को समुचित राहत मिलेगी और छत्तीसगढ़ कृषि उत्पादन में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।

सरकारी पहल से किसान संतुष्ट

किसान समितियों में आसानी से खाद उपलब्ध करा पा रहे हैं और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इससे खेती-किसानी प्रभावित होने के बजाय और मजबूती पा रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, किसानों ने सरकार और प्रशासन की इस पहल पर संतोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि समय पर यूरिया और अन्य खाद उपलब्ध होने से बुवाई और फसल प्रबंधन का काम सुचारू रूप से हो रहा है।

खाद की समयबद्ध आपूर्ति ही प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि, खरीफसीजन में किसानों को खाद की आपूर्ति उनकी समयबद्ध जरूरतों के अनुरूप प्राथमिकता से की जा रही है। अब तक निर्धारित लक्ष्य का 98 प्रतिशत यूरिया किसानों तक पहुँच चुका है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि, किसानों को मौसम और फसल की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त खाद की आपूर्ति लगातार जारी रहेगी और उनकी उपज सुरक्षित रहेगी।

मंत्री नेताम और सांसदों ने की पहल

इस संबंध में गत दिनों कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम और राज्य के सांसदों ने भी केंद्रीय उर्वरक मंत्री श्री जे.पी. नड्डा से भेंट कर छत्तीसगढ़ के किसानों की मांग रखी थी। मुख्यमंत्री श्री साय के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार से लगातार संपर्क किया गया और किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त 60 हजार टन यूरिया का आबंटन स्वीकृत किया गया। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में सहकारी सोसायटियों और निजी विक्रेताओं के माध्यम से खाद का वितरण सुव्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है।

जीएसटी में सुधारों का अमूल ने किया स्वागत
पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर के कदम को सराहा

जीएसटी में नई कटौती से डेयरी क्षेत्र को मदद मिलने पर प्रधानमंत्री और अमूल के बीच गर्मजोशी से बातचीत हुई

नई दिल्ली। अमूल ब्रांड के मालिक जीसीएमएमएफने सरकार के व्यापक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया। डेयरी सहकारी समितियों का कहना है कि इस कदम से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को ही लाभ होगा।

एक्स पर, अमूल ने पोस्ट किया: "अमूल के 36 लाख किसान डेयरी उत्पादों पर जीएसटी में ऐतिहासिक कमी के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हैं। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था में डेयरी क्षेत्र की आधारभूत भूमिका की प्रशंसा करते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की, तथा राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसे सुधारों और मजबूत सहकारी ढांचे के माध्यम से "अन्नदाताओं" के लिए प्रशासन के समर्थन को सुदृढ़ किया। पीएम मोदी ने जीएसटी में बदलाव को "लाखों डेयरी किसानों को सशक्त बनाने, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और हर घर के लिए डेयरी उत्पादों को अधिक किफायती बनाने" की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बताया।

ग्रामीणों की आय में होगी वृद्धि

विशेषज्ञों और मंत्रालय के अधिकारियों को उम्मीद है कि, इन कर कटौतियों से ग्रामीण आय में वृद्धि होगी, घरों में डेयरी उत्पादों को अपनाने में तेजी आएगी, तथा लाखों छोटे किसानों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। इन सुधारों के साथ, सरकार एक स्पष्ट संदेश देती है: डेयरी क्षेत्र, जो भारत की कृषि रीढ़ का प्रतीक है, पोषण सुरक्षा, आर्थिक समावेशन और ग्रामीण समृद्धि को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमूल और प्रधानमंत्री के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत न केवल प्रभावी सार्वजनिक-निजी सहयोग को उजागर करती है, बल्कि विचारशील कर नीति की परिवर्तनकारी क्षमता को भी रेखांकित करती है।

जीएसटी से 12 और 28 प्रतिशत के स्तर समाप्त

जीएसटी 2.0 के युक्तिकरण में एक सरलीकृत संरचना पेश की गई है, जिसमें कर स्लैब को केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत तक समेकित किया गया है, पुराने 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के स्तरों को समाप्त कर दिया गया है, और विलासिता और "पाप" वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत कर आरक्षित किया गया है। उल्लेखनीय है कि अधिकांश डेयरी उत्पादों पर अब या तो शून्य जीएसटी दर लागू होगी या केवल 5 प्रतिशत कर लगेगा, जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए एक बड़ी राहत है। उदाहरण के लिए, अल्ट्रा-हाई-टेम्परेचर (UHT) दूध और पैकेज्ड पनीर को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है, जबकि मक्खन, घी, पनीर, कंडेंस्ड मिल्क, आइसक्रीम और डेयरी उत्पादों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटकर केवल 5 प्रतिशत रह गया है। दूध के डिब्बों पर भी इसी तरह कम कर लगाया गया है।

डेयरी प्रोडक्ट की खपत में आएगी तेजी

22 सितंबर, 2025 से प्रभावी इन परिवर्तनों से भारत के 19 लाख करोड़ रुपये के डेयरी क्षेत्र में खपत में उल्लेखनीय वृद्धि और मांग में तेजी आने की उम्मीद है। मीडिया से बातचीत में अमूल की मूल संस्था (जीसीएमएमएफ) के प्रबंध निदेशक जयेन मेहता ने कहा, "अमूल से जुड़े 36 लाख किसान परिवारों और व्यापक डेयरी पारिस्थितिकी तंत्र में 10 करोड़ से अधिक परिवारों की ओर से, समाज इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए पीएम मोदी और एफएम सीतारमण का आभारी है," उन्होंने कहा कि 30 से अधिक डेयरी और खाद्य श्रेणियां नए जीएसटी कटौती से लाभान्वित हुई।

जीएससीसीएसएफ की वार्षिक आम बैठक

फेडरेशन के अध्यक्ष अमीन बोले- सहकारी ऋणों से छोटे और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाना चाहिए

■ **गुजरात राज्य सहकारी ऋण समिति संघ ने अहमदाबाद में 29वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित**

अहमदाबाद। गुजरात राज्य सहकारी ऋण समिति संघ लिमिटेड (जीएससीसीएसएफ) की 29वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सहकारी ऋण समितियों में पेशेवर प्रबंधन की आवश्यकता पर केंद्रित एक कार्यक्रम के साथ 31 अगस्त, 2025 को सहयोग, रिलीफ रोड, अहमदाबाद में आयोजित की गई।

फेडरेशन के अध्यक्ष घनश्याम भाई एच. अमीन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और छोटे और मध्यम वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सहकारी गतिविधियां 120 से अधिक देशों में फल-फूल रही हैं, जिन्हें वैश्विक स्तर पर सतत आर्थिक विकास के लिए प्रभावी उपकरण के रूप में मान्यता प्राप्त है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी पुष्टि की गई है।

लाभांश वितरण सीमा बढ़ाने की सराहना

समकालीन विकास पर विचार करते हुए उन्होंने बताया कि, PACS उप-नियमों में संशोधन से अब उन्हें मेडिकल स्टोर और टिकट बुकिंग से लेकर गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों तक 22 विभिन्न सेवाएं प्रदान करने की अनुमति मिल गई है। जिससे उन्हें अपने व्यवसाय के दायरे को पेशेवर रूप से विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहन मिला है। गुजरात सरकार द्वारा लाभांश वितरण सीमा को 15% से बढ़ाकर 20% करने और सदस्यों को उपहार की सीमा बढ़ाने के निर्णय की भी सराहना की गई। उन्होंने ऋण समितियों से आह्वान किया कि वे लघु वित्त बैंकों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अपने कार्यों का आधुनिकीकरण करें, विशेष रूप से जमा योजनाओं, ब्याज दरों और ऋण व्यवस्थाओं में संशोधन करके।

सहकारिता को महिलाओं और युवाओं तक पहुंचाना है

संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को पुनः "अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष" के रूप में घोषित किया है, जिसका विषय है "सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है", जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित एक वैश्विक सम्मेलन में लॉन्च किया गया। अमीन ने इस बात पर जोर दिया कि ऋण समितियों की जिम्मेदारी सहकारी गतिविधियों को व्यापक रूप से बढ़ावा देना, जन जागरूकता बढ़ाना तथा यह सुनिश्चित करना है कि लाभ जमीनी स्तर पर लोगों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं तक पहुंचे, ताकि उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रेरित किया जा सके।

जिला सहकारी संघ धमतरी की सातवीं वार्षिक आमसभा संपन्न

वार्षिक प्रतिवेदन का हुआ पठन, अतिथियों ने किया संबोधित

धमतरी। आनंद उत्सव भवन रायपुर रोड धमतरी में 3 सितंबर को जिला सहकारी संघ का सातवां वार्षिक आमसभा संपन्न हुई। संघ के प्राधिकृत अधिकारी सीपी साहू की अध्यक्षता एवं प्रदीप ठाकुर उपायुक्त सहकारिता धमतरी, बलरामपुरी गोस्वामी नोडल अधिकारी कोऑपरेटिव बैंक धमतरी परिक्षेत्र, राकेश चंदवानी पार्षद एवं अखिलेश सोनकर सभापति जल विभाग नगर निगम धमतरी, नरेंद्र साहू पैक्स प्रबंधक संघ प्रदेश अध्यक्ष की गरिमामयी उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। आमसभा का शुभारंभ मंचस्थ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन व भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण उपरांत किया गया।

कार्यक्रम में संघ के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन का पठन किया गया, पश्चात उपायुक्त सहकारिता श्री ठाकुर ने कहा कि, जिला सहकारी संघ जिला स्तर पर सहकारी आंदोलन के मान्य प्रचारक प्रतिनिधि संस्था के बतौर जिले में लगातार अपने उद्देश्यों के तहत बेहतर कार्य कर रहा है। उन्होंने विस्तार पूर्वक जिले में कार्यरत सहकारी समितियो की जानकारी से अवगत कराया। कार्यक्रम को नोडल अधिकारी तथा मंचस्थ अतिथियों ने भी संबोधित किया।

इन विषयों पर भी लिया गया निर्णय

इसके साथ ही पैक्स द्वारा जिला संघ को देय वर्ष 23-24 व वर्ष 24-25 के अभिदाय राशि को कोऑपरेटिव बैंक में जमा करने के बाद भी संघ को अब तक जमा राशि अप्राप्त होने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि, कोऑपरेटिव बैंक को ब्याज व मूल जमा राशि का भुगतान शीघ्र पत्राचार करने स्वीकृति दी गई। साथ ही वर्ष 25-26 का संघ को देय अभिदाय राशि को कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से जमा न करने का निर्णय लिया गया। सीधे समितियों द्वारा जिला संघ के खाते में भुगतान करना स्वीकार किया गया, साथ ही संघ कार्यालय सह प्रशिक्षण केंद्र भवन हेतु भूमि की मांग अथवा क्रय किया जाना सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया तथा यह भी स्वीकार किया गया कि वृहद स्तर पर जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति में पैक्स के प्राधिकृत अधिकारियों तथा प्रबंधकों का संयुक्त रूप से सम्मेलन आयोजित किया जावे।

प्रस्तावित कार्यक्रमों का हुआ अनुमोदन

संघ के प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से संघ प्रबंधक द्वारा आम सभा में जारी विषय सूची के अनुसार पिछली आम सभा की बैठक में पारित प्रस्ताव व निर्णय की पुष्टि का अनुमोदन, वर्ष 23-24 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों सहित अंकेक्षण आक्षेप से निराकरण का अवगत व अनुमोदन, वर्ष 24-25 के अअंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन व वर्ष 25-26 के वार्षिक बजट का अनुमोदन, वर्ष 25-26 के लेखाओं की संपरीक्षा पंजीयक द्वारा अनुमोदित पैनल से कराए जाने के साथ वर्ष 24-25 में हुए प्रचार प्रसार कार्यक्रम तथा वर्ष 25-26 के प्रस्तावित कार्यक्रम का सर्वसम्मति से सहमति व स्वीकृति प्रदान कर अनुमोदन किया गया।

इनकी भी रही मौजूदगी

इस अवसर पर सहकारिता विभाग के सहकारी निरीक्षक अरविंद मिश्रा, भुनेश्वर नेताम, गुणेश वैष्णव, तोषी भुआर्य, सहकारिता विस्तार अधिकारी जितेंद्र नंदा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एस प्रसाद, श्रीमती पूर्णिमा घाणेकर सहित कर्मचारी तथा पैक्स, दुग्ध, मत्स्य व वनोंपज समितियो से जुड़े संघ प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आमसभा का संचालन एवं आभार प्रदर्शन संघ प्रबंधक ए पी गुप्ता ने किया।

दुग्ध सहकारी समितियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए दिया गया प्रशिक्षण

दुधारू पशुओं में बीमारियां और नस्ल सुधार के बारे में भी समझाया गया

बलौदाबाजार। कलेक्टर श्री दीपक सोनी के मार्ग दर्शन में जिला के 99 पंजीकृत दुग्ध सहकारी समितियों का सहकारिता विभाग एवं जिला सहकारी संघ मर्यादित बलौदाबाजार-भाटापारा के तत्वाधान में 12 सितंबर को एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में पशुधन विकास विभाग से डॉ. नरेन्द्र सिंह उप संचालक एवं डॉ. रुपेश बघेल के द्वारा विभाग में संचालित योजनाओ की संक्षिप्त जानकारी देते हुए सहकारी समिति के सदस्यों को पशुओं में होने वाले बीमारियों जैसे- खुरहा, चपका, एकटगीया, गलघोटू, लम्पी स्किन रोग होने पर पशुओं को अनिवार्य रूप से टीकाकरण कराने जानकारी दी गई। उन्नत नस्ल सुधार हेतु अच्छी नस्ल के देशी गाय, सहवाल एवं जर्सी तथा अन्य उन्नत नस्लों के गाय-भैंस का कृत्रिम गर्भाधान (AI) कराने हेतु सदस्यों को प्रोत्साहित किया गया द्य कार्यशाला में कृषको को चारागाह निमार्ण कर नेपियर घास तथा मक्के एवं बाजरे जैसे हरे चारा का पशु आहार में उपयोग करने हेतु जानकारी दी गई, विभाग के द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1962के माध्यम से मोबाइल वेन की सुविधा उपलब्ध है तथा पशुओ में आपातकालीन स्थिति तथा विभाग योजनाओ की जानकारी प्रदाय की जा रही है कृषको को अपने पशुओ को घर में बांध कर रखे खुला ना छोड़ने की अपील किया गया।

दुग्ध समितियों की दी गई विस्तार से जानकारी

कार्यशाला में जिले के अंतर्गत पंजीकृत दुग्ध समितियों के द्वारा प्रतिदिन समिति सिमगा में 300 लीटर, खिलोरा 100 लीटर, कौवाडीह में 300, ओडान 250 लीटर, चन्दन 150 लीटर, रंगोरा 150 लीटर, पासिद 200 लीटर अकलतरा में 150 लीटर दुग्ध का उत्पादन कर विक्रय कर छग राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ रायपुर को करने की जानकारी दी गई, जिससे की समिति को प्रतिमाह 10-12 लाख की आय-व्यय होने की जानकारी दी गई। कौवाडीह समिति के पशुपालक कृषक श्री नवीन वर्मा ने बताया कि, वे समिति में प्रतिदिन 100 लीटर दुग्ध का बिक्री कर रहे है जिससे की प्रतिदिन 3500 रूपये का एवं मासिक 105000.00 का आमदनी हो रही है साथ ही अन्य कृषक श्री घनश्याम यदु को प्रतिमाह 70000.00 , सुभाष यदु को प्रतिमाह 50000.00, मोहन यदु को प्रतिमाह 35000.00 रूपये दुग्ध बिक्री से प्राप्त होने की जानकारी दी गई। सहकारी समिति से जुड़कर के स्थानीय स्तर पर उनके द्वारा उत्पादित दुग्ध का बिक्री समिति में होने पर कृषकों द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई।

कार्यक्रम में इनकी भी रही मौजूदगी

कार्यक्रम में उप आयुक्त श्री उमेश गुप्ता, डॉ. नरेन्द्र सिंह उप संचालक एवं डॉ. रुपेश बघेल, नोडल अधिकारी श्री जी एन साहू, श्री के बी वारे, श्री डी के नेताम, श्री एम एस कँवर एवं जिले के दुग्ध सहकारी समिति के अध्यक्ष, सचिव उपस्थित रहे।

आयुक्त ने कार्यप्रणाली से कराया अवगत

उप आयुक्त श्री उमेश कुमार गुप्ता द्वारा सहकारी समितियों की पंजीयन, कार्यप्रणाली, निर्वाचन एवं समिति के सदस्यों आपसी समन्वय से नियमित रूप से समिति सदस्यों की बैठक आयोजित करने, आय-व्यय की जानकारी सभी सदस्यों को साझा करने संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। विभाग से संपर्क कर शासन की योजनाओं का लाभ समिति के सदस्यों लेने हेतु प्रोत्साहित किया गया। कार्यशाला में श्री जी एन साहू, नोडल अधिकारी DCCB के द्वारा सहकारी बैंक के माध्यम से दुग्ध सहकारी समितियों को बैंक की योजनाओ के तहत गो-पालन हेतु अल्पकालीन ऋण 02 लाख तक का 1% एवं 3 लाख तक का 03ब्याज दर देने तथा मध्यमकालीन ऋण प्राप्त कर अपने कार्य व्यवसाय मे वृध्दि करने की जानकारी दी गई।

बाढ़ प्रभावित मांदर में सहकारी बैंक की खास पहल

पासबुक वितरण और माइक्रो एटीएम से ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय पिछले दिनों बस्तर संभाग के बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई एवं जमीनी निरीक्षण करते हुए बाढ़ प्रभावित परिवारों को प्रशासन की ओर से किए जा रहे राहत एवं पुर्नवास कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए बाढ़ प्रभावित परिवारों को सभी स्तरों पर संवेदनशीलता एवं तत्परता से प्रशासनिक मदद दिए जाने के निर्देश दिए गए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुपालन में अतिवृष्टि से प्रभावित गाँव मांदर के ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। कलेक्टर बस्तर एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर के प्राधिकृत अधिकारी श्री हरिस एस के द्वारा शाखा लोहंडीगुड़ा और आदिम जाति सेवा सहकारी समिति अलनार ने बाढ़ पीड़ितों को उनके जरूरी दस्तावेज और पैसों तक पहुंचने में मदद की है।

बाढ़ पीड़ितों को मिली बड़ी मदद

बाढ़ के कारण मांदर गाँव के कई घरों का घरेलू सामान बह गया था, जिसमें ग्रामीणों के महत्वपूर्ण दस्तावेज भी शामिल थे। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पासबुक जैसी चीजें शामिल थीं, जिनके बिना सरकारी योजनाओं और बैंक सेवाओं का लाभ उठाना मुश्किल हो रहा था।

किसानों को मिली खेती के लिए राहत

इस पहल से सबसे अधिक फायदा उन ग्रामीण परिवारों को हुआ है, जिनकी खेती-किसानी के लिए पैसे निकालने की सख्त जरूरत थी। नई पासबुक मिलने से वे अब अपने बैंक खाते से आसानी से रकम निकाल सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी फसल और खेती से जुड़े कार्यों को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। इस मुश्किल घड़ी में बैंक और समिति द्वारा किए गए इस प्रयास ने ग्रामीणों को एक बड़ा सहारा दिया है, जिससे वे अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर

पासबुक और माइक्रो एटीएम से हुआ भुगतान

ग्रामीणों की इस समस्या को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लोहंडीगुड़ा ने गाँव में ही नवीन बैंक पासबुक का वितरण किया गया। इसके साथ ही आदिम जाति सेवा सहकारी समिति अलनार ने माइक्रो एटीएम मशीन की व्यवस्था की है। इसके माध्यम से जिन किसानों के पास एटीएम कार्ड था, उन्हें तत्काल उनकी जरूरत के अनुसार नकदी का भुगतान किया जा रहा है।

वन विभाग की समीक्षा : मंत्री केदार कश्यप बोले- स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर देने पर विशेष जोर रखें

वन आधारित रोजगार सृजन एवं वनों के संरक्षण हेतु कार्ययोजना के अनुरूप करें पहल

जगदलपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में आज जगदलपुर स्थित वन विद्यालय के सभाकक्ष में वन विभाग के विभिन्न कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में वृक्षारोपण, कूप कटाई, निर्माण कार्य, राजस्व संग्रहण, वनों के संरक्षण तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही, ग्रामीणों की आय में वृद्धि के लिए विभाग द्वारा संचालित प्रयासों की गहन समीक्षा की गई। वन मंत्री श्री कश्यप ने बैठक में कहा कि वनों के संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय ग्रामीणों विशेषकर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने पर विशेष जोर दिया जाए। इस दिशा में कार्ययोजना के अनुरूप वृक्षारोपण, सयुंक्त वन प्रबंधन और समुदाय की सहभागिता से वनों की देखभाल और प्रबंधन के लिए व्यापक प्रयास किया जाए। साथ ही लाख पालन, वनोत्पाद पर आधारित प्रसंस्करण एवं ईको टूरिज्म के जरिए रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाए।

वन भूमि पर अतिक्रमण पर त्वरित कार्रवाई करें : कश्यप- वनमंत्री श्री कश्यप ने बैठक में वृक्षों की कटाई और अवैध परिवहन पर नजर रखने और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वन भूमि पर अतिक्रमण पर त्वरित कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि वनौषधि के संरक्षण के साथ ही वैद्यों के परंपरागत ज्ञान का उपयोग कर उनकी भूमि में वनौषधियों का रोपण करें तथा वन भूमि के तालाबों का उपयोग मछली पालन हेतु करें और स्थानीय युवाओं को रोजगार दें। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण के साथ ही पौधों की देखभाल और वृक्षों का संरक्षण हमारा दायित्व है। इस दायित्व का निर्वहन भली भांति करें। योजना बनाकर कार्य को पूर्ण करें।

वनोपज वनवासियों की आजीविका का आधार : कश्यप

इस अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि, वनोपज वनवासियों की आजीविका का आधार है। इको टूरिज्म और वनोपज प्रसंस्करण के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दें। बस्तर कई दशकों से माओवाद से पीड़ित रहा है, किंतु अब माओवाद के साए से बाहर आ रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर के विभिन्न पर्यटन स्थानों पर सुविधाएं प्रदान करते हुए स्थानीय युवाओं को रोजगार दें। पर्यटन स्थानों के विकास में स्थानीय परंपराओं का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि लघु वनोपज के प्रसंस्करण का लाभ स्थानीय युवाओं को मिले। नीलगिरी और अकेशिया के विदोहन के लिए आवश्यक नीति निर्माण हेतु तत्परता से कार्य करें। वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के पश्चात तत्काल वृक्षारोपण करें।

योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पेश हुई

बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण अभियान के तहत लाखों पौधे रोपे जा चुके हैं, जबकि कूप कटाई और निर्माण कार्यों में भी तेजी आई है। राजस्व संग्रहण में वृद्धि दर्ज की गई है और मालिक मकबूजा योजना के माध्यम से वनवासियों को उनके अधिकार सुनिश्चित किए जा रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लघु वनोपज संग्रहण और वैकल्पिक आजीविका स्रोतों पर फोकस किया गया, ताकि ग्रामीणों की आय दोगुनी हो सके।

बस्तर में विकास की नई लहर : कश्यप

वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि, बस्तर क्षेत्र में माओवाद के खात्मे के बाद विकास की नई लहर चल रही है और वन विभाग को इसमें अग्रणी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए। वन मंत्री श्री कश्यप ने बस्तर के नियद नेल्लनार योजना क्षेत्रों में वन विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित करने सहित नियमित रूप से मॉनिटरिंग किए जाने की बात कही।

इन अफसरों की रही मौजूदगी

बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री व्ही. श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ श्री अनिल साहू, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी श्री अरुण पाण्डे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री ओपी यादव, मुख्य वन संरक्षक श्री आरसी दुग्गा, मुख्य वन संरक्षक कांकेर श्री दिलराज प्रभाकर, मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी जगदलपुर सुश्री स्टाइलो मंडावी, तीनों वन वृत्त के सभी वन मंडलाधिकारी एवं उप वन मंडलाधिकारी उपस्थित रहे।

दिव्यांग खिलाड़ियों ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान

- ग्वालियर स्थित अटल बिहारी वाजपेई दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र
- महासमुंद के पैरा एथलीट्स की चमक, राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जीते 5 पदक

रायपुर। ग्वालियर स्थित अटल बिहारी वाजपेई दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र में 29 से 31 अगस्त तक आयोजित 14वीं जूनियर एवं सब-जूनियर नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में महासमुंद जिले के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए शानदार प्रदर्शन किया। समाज

कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त संस्था फॉर्च्यून फाउंडेशन कर्मापटपर, बागबाहरा के पाँच खिलाड़ियों ने कुल पाँच पदक जीतकर जिले का मान बढ़ाया।

जूनियर पुरुष वर्ग की टी-11 कैटेगरी में सुखदेव ने 400 मीटर और 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल कर सबका ध्यान खींचा। वहीं, टी-12 कैटेगरी में निखिल कुमार यादव ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर जिले को गौरवान्वित किया। इसी प्रतियोगिता में सब-जूनियर महिला वर्ग की टी-12 कैटेगरी में नीलम टंडन ने 400 मीटर दौड़ में रजत पदक प्राप्त किया। इसके साथ ही टी-11 कैटेगरी में देवमोती ने लॉन्ग जम्प में कांस्य पदक जीता। नोशन लाल पटेल ने भी टी-2 कैटेगरी की 1500 मीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया।

संस्था के संस्थापक एवं राष्ट्रीय टीम के प्रशिक्षक व मैनेजर निरंजन साहू ने बताया कि दल में तीन बालक और दो बालिका खिलाड़ी शामिल थे, जिनके साथ कोच-मैनेजर और गाइड रनर देवेंद्र ठाकुर व मेघराज यादव तथा सहायक स्टाफ दिव्य लोचन और रश्मि साहू भी मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि सुखदेव इससे पहले 11-12 जुलाई 2025 को बेंगलूरु में आयोजित 7वीं ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं।

धमतरी की स्वर्णिम कृषि यात्रा : आत्मनिर्भरता और समृद्धि के 25 वर्ष

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मध्य में बसा धमतरी जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता है। 06 जुलाई 1998 को रायपुर और महासमुंद जिलों से विभाजित होकर स्थापित धमतरी ने पिछले 25 वर्षों में अपने आत्मनिर्भरता और समृद्धि में उल्लेखनीय प्रगति की हैं। जिले के किसानों ने परंपरागत खेती से आगे बढ़कर आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधाओं और शासन की योजनाओं का लाभ उठाया हैं। परिणामस्वरूप उत्पादन, क्षेत्रफल और किसानों की आय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जो जिले की कृषि क्षमता और मेहनतकश किसानों की जीवंत गाथा को दर्शाती है।

इस जिले का प्रमुख खरीफ फसल धान रही है। वर्ष 2000 में खरीफ का क्षेत्रफल 1,37,575 हेक्टेयर था, जो 2025 में लगभग स्थिर रहते हुए 1,35,886 हेक्टेयर रहा। इसके विपरीत रबी फसलों का क्षेत्र 40,930 हेक्टेयर से बढ़कर 60,620 हेक्टेयर हो गया, जो 48.11 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। यह प्रगति आधुनिक सिंचाई साधनों और किसानों की नई सोच का परिणाम है।

दलहन और तिलहन उत्पादन में भी जिले ने ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल कीं। रबी दलहन

का क्षेत्र 10,570 हेक्टेयर से बढ़कर 32,290 हेक्टेयर तक पहुँचा, जिसमें 205.49 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसी प्रकार रबी तिलहन में 498.04 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि हुई। यह परिवर्तन जिले को खाद्यान्न एवं तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहा है।

सिंचाई विस्तार कृषि उन्नति का आधार बना। खरीफ का सिंचित क्षेत्र 87,390 हेक्टेयर से बढ़कर 1,20,026 हेक्टेयर हुआ, वहीं रबी में 32,500 हेक्टेयर से बढ़कर 74,490 हेक्टेयर तक पहुँचा, जो 129.20 प्रतिशत की वृद्धि है। इससे रबी फसलों की उत्पादकता और स्थिरता में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

बीज और उर्वरक वितरण व्यवस्था भी सुदृढ़ हुई है। वर्ष 2025 में 60,895 क्विंटल बीज और 26,950 टन उर्वरक वितरित किए गए। फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ में 10,864.4 हेक्टेयर और रबी में 5,445 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया, जिससे किसानों को जोखिम प्रबंधन का मजबूत साधन मिला।

जैविक खेती में भी अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई है। खरीफ में जैविक क्षेत्र 1,180 हेक्टेयर से बढ़कर 1,680 हेक्टेयर और रबी में 100 हेक्टेयर से बढ़कर 250 हेक्टेयर हो गया। यह बदलाव पर्यावरण संरक्षण और सतत कृषि की दिशा में किसानों की जागरूकता को दर्शाता है। किसानों की आय संवर्धन हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जिले के 1,02,036 कृषक लाभान्वित हुए।

मुख्यमंत्री साय ने जशपुर जिले में चार उच्च स्तरीय पुल निर्माण को दी मंजूरी

- **अब जान जोखिम में डाल कर नहीं करना पड़ेगा नदी पार**
- **मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जिले में चार उच्च स्तरीय पुल निर्माण को दी मंजूरी**
- **विकास की सौगातों से बदल रही है जशपुर की तस्वीर**

जशपुरनगर। जिलेवासियों के लिए आवागमन को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सड़क और पुल-पुलिया का तेजी से विकास कर रहे हैं। जिले में पुल-पुलिया की कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री श्री साय ने चार वृहद पुल निर्माण के लिए 13 करोड़ 46 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। इनमें गुलझरिया बम्हनी मार्ग पर श्री नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण शामिल है। पुलविहिन इस नदी पर पुल निर्माण करने का मांग ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से किया जा रहा था। बरसात के दिनों में इस नदी को पार करने में ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को दूर करने के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने श्री नदी पर पुल निर्माण के लिए 3 करोड़ 66 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। इस पुल के निर्माण से गुलझरिया से बम्हनी के बीच

बसे लगभग दर्जन भर गांव के रहवासियों का विकासखंड मुख्यालय दुलदुला तक पहुंच आसान हो जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच कनेक्टिविटी के लिए एक और वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा। इसके अलावा सीएम श्री साय ने जिले में 1.71 करोड़ की लागत से बेनसारी नाला में किलकिला से केराकछार रोड में पुल पुलिया का निर्माण,मैनी नदी में कांसाबेल से शब्दमुंडा मार्ग में जर्जर पुलिया के जगह नए पुल निर्माण के 3.49 करोड़ की लागत से निर्माण किया जा रहा है और जिला मुख्यालय जशपुर में बांकी नदी पर जर्जर पुल हो चुके पुल की जगह नए उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए 4 करोड़ 60 लाख की स्वीकृति दी है।

'जिले में विकसित हो रहा है बुनियादी ढांचा '

किसी भी जिले के लिए विकास का पैमाना बुनियादी ढांचा को माना जाता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के गृह जिले में बीते दो साल के अंदर इस क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है। सड़क व पुल के साथ ही शिक्षा,स्वास्थ्य,पानी की सुविधा विकसीत कर,आम नागरिकों का जीवन सुखद बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार जशपुर जिले के लिए दिल खोल कर बजट दे रही है। सरकार का

हिन्दी हो या अंग्रेजी, सभी विषयों की पढ़ाई में आई तेजी

- **युक्तियुक्तकरण से लैंगी हाई स्कूल को मिले व्याख्याता**

रायपुर। राज्य शासन द्वारा शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया ने दूरस्थ अंचलों के विद्यालयों की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कोरबा जिले के अति दूरस्थ ग्राम लैंगी के हाई स्कूल को वर्षों बाद हिन्दी और अंग्रेजी विषय के व्याख्याता प्राप्त हुए हैं। इससे विद्यार्थियों में नया उत्साह है तथा अब उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है।

वर्ष 2011 में स्थापित लैंगी हाई स्कूल केवल एक गाँव ही नहीं बल्कि आसपास के अनेक ग्रामों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का केंद्र रहा है। अमझर, पोड़ी कला, दुल्लापुर, तराई नार, पिपरिया, इमली बरहा, कोड़गार सहित कई गाँवों से बच्चे यहां पढ़ाई करने आते हैं। वर्तमान में विद्यालय में कक्षा 9वीं और 10वीं के कुल 46 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विद्यालय के प्राचार्य श्री श्यामलाल अश्विनी बताते हैं कि स्थापना से अब तक हिन्दी और अंग्रेजी विषय के व्याख्याता उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती थी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की गई युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से इस कमी की पूर्ति हो गई है। विद्यालय को हिन्दी विषय के व्याख्याता श्री दिनेश कुमार यादव एवं अंग्रेजी विषय के व्याख्याता श्री विनोद कुमार साहू उपलब्ध कराए गए हैं। दोनों ही शिक्षक नियमित रूप से कक्षाएं लेकर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

विद्यालय के विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों में इस बदलाव को लेकर खुशी है। कक्षा 10वीं की छात्राओं समीना, कल्याणी और सोनी मार्को का कहना है कि

पहले हिन्दी और अंग्रेजी के शिक्षक न होने से पढ़ाई में कठिनाई आती थी, परंतु अब नियमित कक्षाएं हो रही हैं। कक्षा 9वीं के विद्यार्थी दीपक का कहना है कि अब गणित, विज्ञान सहित सभी विषयों के शिक्षक उपलब्ध हैं, जिससे पढ़ाई में गति आई है। शिक्षकों की उपलब्धता से न केवल अध्यापन व्यवस्था सुचारु हुई है, बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं में भी आत्मविश्वास और पढ़ाई के प्रति लगाव बढ़ा है। ग्रामीणों का मानना है कि यह पहल उनके बच्चों को बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करेगी।

डबल सब्सिडी से छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा का उजाला

रायपुर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रदेश सरकार के प्रत्यक्ष सहयोग से दोगुना लाभ मिल रहा है। डबल सब्सिडी और हाफ बिजली से मुफ्त बिजली की ओर छत्तीसगढ़ का संकल्प अब साकार होने लगा है। इस योजना से न केवल बिजली का खर्च कम होगा, बल्कि आम नागरिकों के लिए अतिरिक्त आय का साधन भी उपलब्ध होगा।

आवासीय मकानों की छतों पर सौर पैनल स्थापित कर स्वच्छ, किफायती और स्थायी ऊर्जा उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। वर्ष 2024 में घोषणा के बाद यह योजना देशभर में लागू की गई और अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसमें अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की है। पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा 60 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही थी। राज्य सरकार की भागीदारी से यह राहत और बढ़ गई है। उदाहरणस्वरूप, 3 किलोवाट क्षमता के सौर पैनल की कुल लागत लगभग 1.50 लाख रुपये होती है। डबल सब्सिडी के पश्चात उपभोक्ताओं को अब केवल 30 से 40 हजार रुपये का व्यय करना होगा। योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बैंकों से 6.5 प्रतिशत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे मासिक ईएमआई इतनी किफायती होगी कि यह मौजूदा बिजली बिल से भी कम साबित होगी। कुछ वर्षों पश्चात उपभोक्ता को जीवनभर मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। घर में आवश्यकता से अधिक उत्पादित बिजली राज्य की वितरण कंपनियों को ग्रिड के माध्यम से बेची जा सकेगी। यह व्यवस्था विशेषकर ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त आय एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता का साधन बन रही है। यह योजना केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी लाभकारी है। प्रत्येक घर ÷ग्रीन एनर्जी हब÷ के रूप में विकसित हो रहा है तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है, वहां सौर ऊर्जा के माध्यम से निर्बाध एवं स्वच्छ बिजली उपलब्ध होगी।

मेहनत, धैर्य और कौशल से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है: विजेता

- **विजेता बनी मेहनत, तकनीक और आत्मनिर्भरता की मिसाल**
- **कोसा बीज उत्पादन में हासिल की उपलब्धि, केंद्रीय रेशम बोर्ड से मिला सम्मान**

रायपुर। विजेता कोरी ने आज अपने नाम के अनुरूप विजेता बनकर अपने नाम को सार्थक बना दिया है और यह सिद्ध कर दिया है कि मेहनत, धैर्य और कौशल से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। वे अब न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। ग्राम रमतला की विजेता रामसनेही उर्फ अन्नू कोरी आज ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। साधारण परिवार से आने वाली अन्नु ने मेहनत और लगन से न केवल अपनी आजीविका को सशक्त बनाया बल्कि पूरे क्षेत्र में रेशम उत्पादन के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने एक माह में 12 हजार कोसा बीज का उत्पादन किया। केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा विजेता को उनकी उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया।

मेहनत, धैर्य और कौशल से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है-विजेता

बिलासपुर जिला के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रमतला निवासी श्रीमती विजेता कोरी उर्फ अनु पिछले 10 वर्षों से रमतला रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र से जुड़ी हुई हैं। प्रारंभ में उन्हें इस कार्य की जानकारी नहीं थी, लेकिन केंद्र से मिले प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन ने उनके भीतर आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने धीरे-धीरे रेशम और कोसा बीज उत्पादन की बारीकियों को सीखी। विजेता ने बताया कि रेशम उत्पादन की प्रक्रिया बेहद कठिन है और कड़ा परिश्रम करनी पड़ती है, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। दिन-रात मेहनत कर कोसा बीज उत्पादन किया और अकेले ही 12 हजार से अधिक बीज का निर्माण किया।

हाल ही में केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कोरबा जिले के पाली विकासखंड के ग्राम डोंगानाला में आयोजित कार्यक्रम मेरा रेशम, मेरा अभिमान में केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उन्होंने मात्र एक माह में 12 हजार नग कोसा बीज तैयार कर रिकॉर्ड बनाया। इस कार्य से उन्होंने 40 हजार रुपये की आमदनी अर्जित की, विजेता ने अकेले यह उपलब्धि हासिल की। यह उपलब्धि उनकी मेहनत, कौशल और आत्मविश्वास का परिणाम है। विजेता कोरी को केंद्रीय रेशम बोर्ड रांची के निदेशक डॉ. एन.बी. चौधरी, बिलासपुर के डॉ. नरेंद्र कुमार भाटिया और श्री सी एस लोन्हारे के हाथों सम्मानित किया गया। यह पहला अवसर था जब उनके कार्य के लिए ऐसा बड़ा सम्मान मिला। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनके लिए अविस्मरणीय है। उन्होंने बताया कि कोसा और रेशम बीज निर्माण की प्रक्रिया में एक माह का समय लगता है और मौसम के अनुकूल वर्ष भर में तीन से चार बार उत्पादन की प्रक्रिया की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि कोसा बीज उत्पादन कार्य के साथ साथ वह केंद्र में समय समय पर दैनिक मजदूरी का काम कर भी आजीविका कमाती हैं। विजेता अपनी मेहनत से मिली आमदनी से अपने परिवार को आर्थिक संबल दिया है। अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और परवरिश दे रही हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का घर मिला। महतारी वंदन योजना से हर माह 1000 रुपए और श्रम विभाग की बीमा योजना सहित कई अन्य योजनाओं, बच्चों को छात्रवृत्ति योजना का भी लाभ मिल रहा है। बिहान के तहत गंगा जमुना स्व-सहायता समूह से जुड़कर उन्होंने मछली पालन का कार्य भी शुरू किया, जिससे उनकी आय के स्रोत बढ़ गए। विजेता कहती हैं - सरकार की मदद से मैंने अपने जीवन को बेहतर बनाया है। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और अपने परिवार को एक सुरक्षित भविष्य दे पा रही हूँ।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में दूरस्थ वनांचलों तक पहुंच रहा सहकारी प्रशिक्षण

बीजापुर जिले के नेलसनार में सहकारी प्रशिक्षण संपन्न

नेलसनार। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर एवं बस्तर जिला सहकारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में आदिवासी सदस्य सहकारी शिक्षा योजना अंतर्गत नक्सल प्रभावित जिला बीजापुर के संवेदनशील क्षेत्र नेलसनार में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित नेलसनार के धान खरीदी केंद्र में सहकारी शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम 12 सितंबर को संपन्न किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में संस्था के प्राधिकारी श्री बुगरू राम के साथ-साथ ग्राम पंचायत नेलसनार के उपसरपंच श्री किशोर नाग विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के दौरान वरिष्ठ प्रशिक्षक विवेक पांडे द्वारा उपस्थित ग्रामीण कृषक सदस्यों को सहकारिता का अर्थ, महत्व ,सिद्धांत के साथ-साथ लेंपस द्वारा प्रदान सेवाओं के विषयों पर विस्तार से ज्ञान करवाया जाकर सहकार से समृद्धि हेतु भारत सरकार द्वारा किए जा रहे पहल पर भी विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण वर्ग के दौरान जिला सहकारी संघ के प्रबंधक श्री सीके द्विवेदी द्वारा राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 के प्रमुख प्रावधानों से भी कृषक सदस्यों को ज्ञान कराया गया।

प्रमुख संस्थानों में प्राधिकारियों के लिए प्रशिक्षण संचालन करने का निवेदन

उप सरपंच ने सहयोग का दिया आश्वासन

किशोर नाग उप सरपंच द्वारा लेंपस की गतिविधियों से परिचित होकर पंचायत का हरसंभव सहयोग लेंपस को प्रदान कर क्षेत्र के खेती किसानी को बढ़ाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने की बात कही गई। प्रशिक्षण को लेंपस नेलसनार के नवनियुक्त प्रबंधक श्री अभिषेक सिंह ठाकुर द्वारा ज्ञानवर्धक बताते हुए भविष्य में भी आयोजित किए जाने हेतु सुझाव दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के कर्मचारी श्री रोकड़े के साथ-साथ संघ के रोमांचल पानीग्राही का सहयोग रहा।

प्रशिक्षण प्राप्ति उपरांत श्री बुगरू राम द्वारा प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण मानते हुए लेंपस के सफल संचालन हेतु प्रदेश या देश के प्रमुख संस्थानों में प्राधिकारियों के लिए प्रशिक्षण संचालित करने हेतु निवेदन किया गया। इस पर प्रशिक्षक विवेक पांडे द्वारा निकट भविष्य में राज्य सहकारी संघ रायपुर या राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर उनकी जानकारी प्रेषित करने की बात कही गई।

कृषक सेवा केंद्र चलाकर लाभान्वित हो रही हैं डोंगरीपारा की महिलाएं

कांदुलगुड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा बस्तर जिले के जगदलपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम कांदूलगुड़ा के आंगनबाड़ी केंद्र में 31 अगस्त को महिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान स्व सहायता समूह एवं ग्रामीण महिलाओं को सहकारिता का अर्थ महत्व सिद्धांत विषय पर विस्तार से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में कांदूलगुड़ा ग्राम की शिव शक्ति, गंगादेई, बमलेश्वरी, सदाफलदेव, मां सीता, मां शीतला समूह के पदाधिकारियों के साथ-साथ ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रहीं।

प्रशिक्षण के दौरान सदाफलदेव महिला स्व सहायता समूह डोंगरीपारा द्वारा समूह के माध्यम से बैंक से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर कृषक सेवा केंद्र के रूप में ट्रैक्टर रोटावेटर थ्रेसर धान कटाई मशीन क्रय कर संचालन करते हुए आय अर्जित करने की जानकारी दी गई। समूह की सफलता की कहानी सुनकर अन्य महिलाएं प्रेरित होकर परंपरागत ढंग से समूह की संचालन हेतु नए तरीकों से ग्रामीण रोजगार हेतु प्रयास करने पर अपने विचार व्यक्त किए। महिलाओं को सहकारी समिति के गठन पंजीयन पर भी विस्तार से जानकारी दिया गया। प्रशिक्षण को सफल बनाने में ग्रामीण श्री भगत राम श्री राम प्रसाद गुड्डू एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ-साथ संघ के रोमांचल पाणिग्राही का सहयोग रहा।

नानगुर लैंपस के किसानों को मिला सहकारी प्रशिक्षण

जगदलपुर। बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर के तत्वाधान में जगदलपुर विकासखंड के ग्राम नानगुर के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित नानगुर में सहकारी प्रशिक्षण संपन्न किया गया। वर्ग के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर के वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री विवेक पांडे के द्वारा किसानों को सहकारिता के अर्थ महत्व सिद्धांत आदि विषय पर विस्तार से ज्ञान करवाया गया एवं लेम्पस में सभी किसानों को सदस्य बनने का आग्रह किया गया एवं शासन के द्वारा कृषि ऋण संबंधी आदि के बारे में विस्तार से बताया गया एवं गोपालन के लिए लेम्पस द्वारा बिना ब्याज के ऋण के लिए जानकारी दिया गया। वर्ग के दौरान सहकार से समृद्धि राष्ट्रीय सहकारी निती 2025 व शासन के विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया। वर्ग को सफल बनाने में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक श्री तुलसी सेठिया एवं लैम्पस कर्मचारी का विशेष सहयोग रहा।

बस्तर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ संभागीय कार्यालय जगदलपुर के तत्वावधान में जिला कोंडागांव के ग्राम बम्हनी के आंगनबाड़ी केंद्र में महिलाओं का एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण का आयोजन प्रशिक्षक मितेश पानीग्राही द्वारा 11 सितंबर को किया गया। जिसमें सहकारिता का अर्थ, महत्व, सिद्धांत, उद्देश्य और विकास सदस्यता सदस्य के अधिकार, कर्तव्य, बैठकें, बैंक लिकिंग, व्यवसाय विकास आदि पर विस्तार से चर्चा दिया गया। जिसे सफल बनाने में संघ के संपर्क साधक श्री करुणाकर मंडन का सहयोग सराहनीय रहा।

कुरेली सहकारी समिति में हुई इफको की किसान सभा

कुरेली। कुरेली सहकारी समिति जिला बिलासपुर में इफ्को द्वारा किसान सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुरेली सहकारी समिति के अध्यक्ष ने की। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में इफ्को राज्य विपणन प्रबंधक श्री आर.के.एस. राठौर, उप-प्रबंधक प्रक्षेत्र श्री नवीन तिवारी, इफको एम.सी से श्री मनीष सिंह एवं समिति प्रबंधक श्री राजेन्द्र कौशिक उपस्थित रहे।

सभा में श्री नवीन तिवारी ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि नैनो यूरिया आधुनिक कृषि का क्रांतिकारी उत्पाद है, जिसमें केवल 500 मि.ली. प्रति एकड़ पर्याप्त होता है और यह 45 किलो दानेदार यूरिया का विकल्प है। इससे लागत घटती है, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और पर्यावरण सुरक्षित रहता है। उन्होंने किसानों से इफ्को के नवीन उत्पादों को अपनाने का आग्रह किया।

श्री आर.के.एस. राठौर द्वारा किसानों को उर्वरकों के सही प्रयोग की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि –धान, गेहूँ जैसी फसलों में नैनो यूरिया का छिड़काव 25–30 दिन एवं 40–45 दिन पर करना चाहिए । यह दानेदार यूरिया का बेहतर विकल्प है। डीएपी (डायअमोनियम फॉस्फेट), फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की पूर्ति करता है और इसे बुवाई के समय बेसल डोज़ के रूप में प्रयोग करना सबसे लाभकारी है। नैनो डीएपी का उपयोग भी किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी है। उन्होंने नैनो डीएपी की जड़ उपचार एवं बीज उपचार विधियों की जानकारी देते हुए किसानों को इसका लाभ उठाने की अपील की। साथ ही उन्होंने बताया की जिंक दानों के भराव और रोग-प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक है, जबकि सल्फर, दलहनों एवं तिलहनों में प्रोटीन और तेल की मात्रा बढ़ाता है। साथ ही नैनो जिंक, नैनो कॉपर एवं बायो-प्रोडक्ट्स के संतुलित उपयोग को भी आवश्यक बताया। सभी किसान भाईयों को इफ्को उत्पादों का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित करते हुये कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हुए।

चेक डैम से सिंचाई के लिए मिलने लगा पर्याप्त पानी

रायपुर। मनरेगा से बनाए गए चेक डैम से किसानों को न केवल सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है, बल्कि इसने जल स्रोतों का जलस्तर भी बढ़ा दिया है। बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड के कोरबी ग्राम पंचायत में पांच लाख 27 हजार रुपए की लागत से मनरेगा से निर्मित चेक डैम ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। गाँव की प्यास बुझाने और खेतों की हरियाली लौटाने में यह अहम साबित हो रहा है। सिंचाई के लिए पानी मिलने से अब यहां के किसान दो से तीन फसलें भी ले रहे हैं।

चेक डैम बनने के बाद क्षेत्र में जल संरक्षण और सिंचाई की स्थिति में बड़ा सुधार आया है। अब मानसून के बाद भी लंबे समय तक पानी उपलब्ध रहता है। खेतों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने लगा है, जलस्तर बढ़ा है और ग्रामीणों को पेयजल संकट से राहत मिली है। खेतों तक समय पर पानी पहुंचने से पैदावार में भी बढ़ोतरी हुई है। कोरबी ग्राम पंचायत का यह चेक डैम जल संचय और जल संरक्षण का सफल उदाहरण बन गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ने दी सुरक्षित छत और जीने का विश्वास : हितग्राही सविता

■ **अपना घर मिला तो मिला जीवन जीने का नया संबल**

बलरामपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों और मुख्यधारा में लौटे आत्मसमर्पित नक्सलियों को अब सुरक्षित छत और सम्मानजनक जीवन मिल रहा है। जनपद पंचायत शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत जोकापाठ निवासी सविता यादव इसका एक सशक्त उदाहरण हैं।

सविता यादव के पति लखन लाल यादव को नक्सलियों ने पुलिस का मुखबिर बताकर निर्ममता से मार डाला था। इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार पर दुःख और भय का गहरा साया छा गया। कठिन हालातों में गुजर-बसर कर रही सविता को प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास स्वीकृत हुआ। उन्होंने समय पर मकान का निर्माण पूरा किया और आज उनके परिवार के सिर पर सुरक्षित छत है। आवास पूर्ण होने के बाद सविता यादव ने भावुक होकर कहा प्रधानमंत्री आवास योजना ने हमें सुरक्षित छत और जीने का विश्वास दिया है। उन्होंने अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा हमारा जीवन भी सामान्य था। पति लखन लाल यादव मेहनत-मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। लेकिन एक दिन नक्सलियों ने उन्हें पुलिस का मुखबिर बताकर मार डाला। यह मेरे लिए असहनीय था। परिवार का सहारा छिन गया, बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब गया और सिर पर सुरक्षित छत तक न रही। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए मुख्यधारा से जोड़ने महत्वपूर्ण पहल की है। जिससे हमें जीवन जीने का नया संबल मिला है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत पीड़ित एवं आत्मसमर्पित परिवारों के लिए आवासों की स्वीकृति प्रदान की। जिसके तहत आज श्रीमती सविता के पास खुद का अपना पक्का मकान है।

छत्तीसगढ़ में ग्रिड पद्धति से खेती कर लिखी सफलता की नई कहानी

■ **किसान रामरतन निकुंज ने रिकॉर्ड पैदावार कर बने प्रेरणास्रोत**

रायपुर। छत्तीसगढ़ में खेती की आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर किसान नई ऊँचाइयाँ प्राप्त कर रहे हैं। कोरबा जिले के झगरहा गाँव के 67 वर्षीय प्रगतिशील किसान श्री रामरतन राम निकुंज ने सेवानिवृत्ति के बाद आधुनिक तरीके से खेती कर सफलता की नई मिसाल कायम की है। उन्होंने वर्मी ग्रिड मैथड से हाईब्रीड धान की खेती में प्रति हेक्टेयर 106 क्विण्टल का उत्पादन प्राप्त किया और प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। श्री निकुंज की मेहनत, नवीन सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने यह साबित किया है कि यदि इरादा दृढ़ हो तो उम्र सफलता के मार्ग में बाधा नहीं बनती। उनकी यह उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है।

श्री रामरतन निकुंज पूर्व में दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड में फोरमेन इंचार्ज के पद पर कार्यरत थे। वर्ष 2018 में सेवानिवृत्त होने के पश्चात् उन्होंने पाँच एकड़ भूमि में आधुनिक और वैज्ञानिक खेती के लिए मॉडल खेत बनाने का संकल्प लिया।

प्रारंभ में कतार बोनी और श्री विधि से धान की खेती करने के बाद वर्ष 2023 से उन्होंने वर्मी ग्रिड मैथड को अपनाया। इस पद्धति में खेत को ग्रिड में विभाजित कर प्रत्येक खंड में वर्मी कम्पोस्ट (केचुआ खाद) का उपयोग किया जाता है। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, पौधों को संतुलित पोषण मिलता है, खरपतवार नियंत्रण के लिए वीडर का उपयोग करने से रासायनिक दवाओं पर निर्भरता घटती है और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इसी पद्धति से वर्ष 2024 में उन्होंने हाइब्रिड धान की खेती की, जिसमें 106 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की रिकॉर्ड पैदावार प्राप्त हुई। इस वर्ष उन्होंने सुगंधित 'देवमोगरा' किस्म पर भी सफल प्रयोग किया है।

खेती में सफलता के पीछे जिला प्रशासन कोरबा और कृषि विभाग का मार्गदर्शन अहम रहा। कृषि अधिकारी श्री कंवर तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री संजय पटेल ने उन्हें समय-समय पर वर्मी ग्रिड मैथड की तकनीक और वैज्ञानिक खेती के तौर-तरीके समझाए। राज्य शासन की योजनाओं से वर्मी कम्पोस्ट संयंत्र, उन्नत बीज और प्रशिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं, जिससे उन्हें नई तकनीक अपनाने में सहायता मिली।

श्री निकुंज न केवल अपनी आमदनी बढ़ाने में सफल रहे, बल्कि उन्होंने आसपास के किसानों को भी इस पद्धति से खेती करने के लिए प्रेरित किया। वे किसानों को जैविक खेती का महत्व समझाते हैं और युवाओं को खेती को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनका मानना है कि खेती अब केवल परंपरागत काम न होकर स्टार्टअप मॉडल बन सकती है। श्री निकुंज की सफलता यह दर्शाती है कि कठोर परिश्रम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शासन की योजनाओं का सदुपयोग करके खेती को लाभकारी और सतत् व्यवसाय में बदला जा सकता है। यह उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम है, बल्कि प्रदेश के समस्त किसानों के लिए अनुकरणीय उदाहरण है।

युक्तियुक्तकरण से विद्यालयों में लौटी रौनक, शिक्षा व्यवस्था हुई सशक्त

■ **खरसिया के 29 एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन शालाओं में हुई शिक्षकों की व्यवस्था**

रायपुर। वर्षों से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे रायगढ़ जिले के खरसिया विकासखंड की विद्यालयों में अब नई उम्मीद दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग की युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया ने न केवल एकल शिक्षकीय व शिक्षकविहीन विद्यालयों की दशा सुधरी है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में ठोस पहल भी साबित हो रही है। प्राथमिक शाला धांगरपारा सरवानी, जहाँ लंबे समय से शिक्षक नहीं थे, अब दो शिक्षकों की तैनाती से बच्चों की पढ़ाई नए उत्साह के साथ शुरू हो चुकी है। इसी प्रकार खरसिया विकासखंड के 29 एकल शिक्षकीय शालाओं में भी शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है, जिससे इन स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था मजबूत हुई है।

युक्तियुक्तकरण से सिर्फ प्राथमिक ही नहीं, बल्कि उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ हुई है। हाईस्कूल पामगढ़, छोटे मूड़पार और नगरपालिका कन्या हायर सेकेंडरी विद्यालय जो वर्षों से विषयवार शिक्षकों की कमी से जूझ रहे थे, अब व्याख्याता शिक्षकों की पदस्थापना से लाभान्वित हो रहे हैं। इससे विद्यालय के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ हो रही है। शासन की इस महत्वपूर्ण पहल से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के सैकड़ों विद्यालयों में आवश्यकता अनुरूप शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। इससे छात्र-शिक्षक अनुपात संतुलित हुआ है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और प्रत्येक विद्यार्थी को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया है। इस पहल से दूरस्थ, आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और शिक्षा की गुणवत्ता का नया संतुलन कायम हो रहा है। यह पहल न केवल खरसिया, बल्कि पूरे रायगढ़ जिले की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

युक्तियुक्तकरण के लिए पालकों एवं छात्रों ने शासन-प्रशासन के प्रति जताया आभार

युक्तियुक्तकरण से पालकों और विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल। ग्राम कोलम चितवाही के पालकों का कहना है कि लंबे समय से जिस बदलाव की प्रतीक्षा थी, वह अब पूरी हो गई है। इससे बच्चों को न केवल नियमित शिक्षा मिल रही है, बल्कि बेहतर वातावरण और सुविधाएँ भी उपलब्ध हो रही है। पालक श्री महेश अगरिया ने बताया कि उनकी दो बालिकाएं है, वे दोनों ग्राम के शासकीय स्कूल में अध्ययन के लिए जाती है। पहले शिक्षक के कमी के कारण उनके दोनों बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही थी, लेकिन युक्तियुक्तकरण से स्कूल में शिक्षकों की पदस्थापना के फलस्वरूप उनकी बच्चियों की पढ़ाई में काफी सुधार आया है। वहीं बालिकाओं ने बताया कि स्कूल में शिक्षक के आ जाने से सभी कक्षाएं नियमित रूप से लग रही है और उन्हें विषयवार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो रही है। उन्होंने स्कूल में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है।

बच्चों और महिलाओं को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं : मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

■ **जशपुर में सखी वन स्टॉप सेंटर, खुला आश्रय गृह, बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण**

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज जशपुर जिले में महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह (बालक), बालिका गृह, खुला आश्रय गृह (बालिका), सखी वन स्टॉप सेंटर में काउंसिलिंग, शयन, भोजन, पेयजल, स्वच्छता, मनोरंजन, सीसीटीवी जैसी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सखी वन स्टॉप सेंटर, खुला आश्रय गृह, बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि बच्चों और महिलाओं के संरक्षण में कोई कमी न रहे, यह राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन संस्था में बेहतर संचालन किया जाए। सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। उन्होंने शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह (बालक) के बच्चों से मुलाकात कर उसे पढ़ाई में मन लगाकर अच्छा आचरण करने की समझाईश दी। उन्होंने अधिकारियों को नियमित परामर्श और मार्गदर्शन की व्यवस्था और मजबूत करने को कहा। बालिका गृह में उन्होंने निवासरत बच्चियों से उनकी दिनचर्या, शिक्षा, भोजन की गुणवत्ता और मीनू पर चर्चा की तथा नियमित सफाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने खुला आश्रय गृह (बालिका) में वसुंधरा विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी में छोटे बच्चों को देखकर उन्होंने उन्हें गोद में लेकर दुलारा और अधिकारियों से बच्चों की देखभाल की विस्तृत जानकारी ली। सखी वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं से चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुनी। उन्होंने नवा बिहान कक्ष एवं काउंसिलिंग सेवाओं का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती रोक्तिमा यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

कृत्रिम पैर मिलने से दिव्यांगों को मिली जीने की नई राह

■ **छात्रा पुलम सहित कलावती, देवा और प्रभु को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में मिले जयपुर कृत्रिम पैर**

रायपुर। शासन की एक छोटी सी मदद से दिव्यांगों के जीने की राह आसान हो गई है। इससे दैनिक कार्यों के संपादन में उन्हें बड़ी सहूलियत हो सकेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज जगदलपुर प्रवास के दौरान ऐसे ही दिव्यांगजनों से मिलकर उनका दर्द साझा किया।

समाज कल्याण विभाग और श्री महावीर विकलांग सहायता समिति के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम आड़ावाल में सहायक उपकरण वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री श्री साय ने दिव्यांगों को जयपुर कृत्रिम पैर एवं हाथ, ट्रायसिकल और अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस दौरान ग्राम साडगुड़ से कक्षा 6वीं की छात्रा कु. पुलम बघेल जो पैर से दिव्यांग है, को जयपुर कृत्रिम पैर वितरित किया गया। कु. पुलम के पिता श्रीधर बघेल ने बताया कि 5 साल की आयु में बेटी का बायां पैर साइकल में फंस जाने के कारण उसमें सेप्टिक हो गया। यहां तक कि बच्ची का पैर कटवाना पड़ गया। उन्होंने बताया कि आज मुख्यमंत्री के समक्ष कृत्रिम पैर मिलने से बिटिया का जीवन आसान हो जाएगा। कृत्रिम पैर मिलने से उसे चलने फिरने, कहीं आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। साथ ही वह खुद से अपने कामों को निष्पादित करने में सक्षम होगी।

इसी तरह तोकापाल ब्लॉक के ग्राम कुरेंगा से आई 23 वर्षीया कु. कलावती मंडावी ने बताया कि जब वह कक्षा आठवीं में अध्ययनरत थीं, तभी उनका बायां पैर करेंट की चपेट में आ गया था और इस घटना से उन्हें अपना पैर खोना पड़ा। मजदूरी करके जीवन चलाने वाली मां देवती बाई के लिए यह दोहरी मार थी। आज कलावती से मिलकर मुख्यमंत्री ने चर्चा की तथा हालचाल जाना। दिव्यांग कलावती ने बताया कि कृत्रिम पैर मिलने से अब उनका जीवन बेहद सुगम और सुविधापूर्ण हो जाएगा। यहां पहुंचे श्री राजू नाग के 07 वर्षीय बेटे देवा को भी समाज कल्याण विभाग और समिति के द्वारा कृत्रिम पैर प्रदान किया गया।

मसानडबरा आवास कॉलोनी बनेगी कमार समाज की पहचान

रायपुर। विशेष पिछड़ी जनजाति कमार समुदाय के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने की दिशा में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना ऐतिहासिक पहल साबित हो रही है। धमतरी जिले के नगरी विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत संकरा के आश्रित ग्राम मसानडबरा में इस योजना के तहत पक्के मकानों का निर्माण किया जा रहा है। यह देश की दूसरी और छत्तीसगढ़ की पहली प्रधानमंत्री जनमन आवास कॉलोनी है, जो कमार समाज के सामाजिक-आर्थिक उत्थान का प्रतीक होगी। मसानडबरा ग्राम पंचायत संकरा से लगभग 5 किमी दूर सुदूर वनांचल में स्थित है। यहाँ मुख्यतः कमार परिवार निवासरत हैं। कुल 42 परिवारों में से 36 पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत मकान स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान में ये परिवार जर्जर कच्चे मकानों में रहते हैं और आजीविका हेतु मुख्यतः वनोपज जैसे महुआ, टोरा, कोसा, कंदमूल, दातून एवं तेंदूपत्ता पर निर्भर हैं।

धमतरी जिले में पीएम जनमन योजना अंतर्गत कुल 1481 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से अब तक

982 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। 1470 हितग्राहियों को 23.90 करोड़ रुपये की राशि प्रदाय की जा चुकी है। मसानडबरा कॉलोनी को एक मॉडल बसाहट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके तहत एक जैसे डिज़ाइन में पक्के मकान, आकर्षक टाइल्स और रंग-रोगन के साथ प्रत्येक घर में स्वच्छ शौचालय और पेयजल सुविधा, प्रत्येक आँगन में फलदार वृक्षारोपण, कॉलोनी में सीसी सड़क, सार्वजनिक उद्यान, बच्चों के लिए झूलाघर और हाईमास्ट लाइट की व्यवस्था की गई है। साथ ही स्थानीय परंपराओं के सम्मान में देवगुड़ी की स्थापना भी की जा रही है।

कमार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न आजीविका गतिविधियाँ जोड़ी गई हैं, जिनमें किराना दुकान, सैलून, सामूहिक मुर्गी पालन और सुअर पालन हेतु शेड निर्माण तथा लिलांज नदी पर स्टॉप डेम बनाकर मछली पालन को बढ़ावा देना शामिल है। इन प्रयासों से न केवल आजीविका के साधन विकसित होंगे बल्कि समुदाय की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। प्रधानमंत्री जनमन आवास कॉलोनी से कमार परिवारों को न केवल सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिलेगा, बल्कि उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भी बड़ा सुधार होगा। आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे और समुदाय मुख्यधारा से जुड़ सकेगा।

कोण्डागांव जिला अस्पताल ने रचा इतिहास, पहली बार लेप्रोस्कोपिक पद्धति से सफल किडनी ऑपरेशन

■ **आर्थिक तंगी झेल रही महिला को मिला नया जीवन**

रायपुर। कोंडागांव जिले ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कोण्डागांव जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने पहली बार लेप्रोस्कोपिक पद्धति से किडनी का सफल ऑपरेशन किया।

कोण्डागांव के बाजारपारा की 35 वर्षीय सावित्री कोर्राम घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू–पोछा और बर्तन धोने का काम करके अपने दो बेटे और दो बेटियों का पालन–पोषण कर रही थी। लेकिन तकदीर ने फिर करवट बदली। दो वर्ष पहले उन्हें गंभीर किडनी रोग की पुष्टि हुई। डॉक्टरों ने तत्काल ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन निजी अस्पताल का खर्च सुनते ही सावित्री की दुनिया जैसे थम गई। आर्थिक स्थिति ने उन्हें मजबूर किया कि वह अधूरे इलाज के साथ घर लौट आएँ। चार बच्चों की परवरिश और घर की जिम्मेदारियों के बीच सावित्री को लगा कि उनकी जिंदगी धीरे-धीरे खत्म हो रही है।

कोण्डागांव जिला अस्पताल बना सहारा

हताशा और निराशा के बीच उन्होंने जिला अस्पताल कोण्डागांव का दरवाजा खटखटाया। अस्पताल के सर्जन डॉ. एस. नगुलन व उनकी टीम ने जांच की और स्पष्ट किया कि उनकी एक किडनी पूरी तरह खराब हो चुकी है, जिसे निकालना ही एकमात्र विकल्प है।

सामान्य ऑपरेशन में बड़े चीरे और संक्रमण का खतरा अधिक था। यह जोखिम उठाना सावित्री के लिए कठिन था। तब डॉक्टर नगुलन ने साहसिक निर्णय लिया ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक तकनीक से किया जाएगा।

जिला अस्पताल से प्राप्त जानकारी अनुसार 4 सितंबर को जिला अस्पताल कोण्डागांव में सावित्री का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन थिएटर में डॉ. एस. नगुलन के साथ डॉ. शैलेश कुमार, डॉ. अनिल देवांगन, डॉ. कृष्णा मरकाम मौजूद थे। ओटी हेड नर्स स्वप्नप्रिया, स्टाफ नर्स पुष्पलता कुंवर, हेमंत मंडावी, संजना जैन, रामेश्वरी, अर्चना, साधना और रीना ने भी अहम भूमिका निभाई। करीब तीन घंटे चले इस ऑपरेशन में सावित्री की खराब किडनी को सफलतापूर्वक निकाला गया। यह ऑपरेशन पूर्णतः सफल रहा और अब सावित्री तेजी से स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। किडनी के सफलतापूर्वक इलाज के बाद सावित्री ने कहा"पहले लगा कि गरीबी और बीमारी ने मेरी जिंदगी खत्म कर दी है। लेकिन जिला अस्पताल और आयुष्मान कार्ड ने मुझे नया जीवन दिया है।"

जल संरक्षण से सोनवर्षा ग्राम के ग्रामीण बने आत्मनिर्भर

रायपुर। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत सोनवर्षा के राधारमण नगर ग्राम में जल संकट लंबे समय से एक गंभीर समस्या बनी हुई थी। भूमिगत जल स्तर 450 फीट से भी नीचे चला गया था, जिससे गर्मियों में ग्रामीणों को पेयजल एवं सिंचाई दोनों के लिए भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इस स्थिति से उबरने हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत खदान के पास नवीन तालाब निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। 12.80 लाख रुपए की लागत से 07 अक्टूबर 2023 को प्रारंभ यह कार्य ग्राम पंचायत की देखरेख में पूर्ण किया गया। निर्मित तालाब ने ग्रामीणों के निस्तार के साथ-साथ कृषि, मत्स्य पालन एवं आजीविका संवर्धन का भी प्रमुख साधन प्रदान किया।

तालाब के निर्माण से ग्रामवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। जहाँ पहले हर गर्मी में जल संकट एक बड़ी चुनौती बनता था, वहीं अब वर्षभर सिंचाई एवं पेयजल हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध है। खेतों में नमी बनी रहने से उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा हरी-भरी फसलें ग्रामीणों की समृद्धि का प्रतीक बन रही हैं। तालाब में मछली पालन प्रारंभ होने से ग्रामीणों को आय का नया स्रोत प्राप्त हुआ है, जिससे वे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुए हैं।

तालाब निर्माण के दौरान तकनीकी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया। बाँध की ऊँचाई एवं चौड़ाई इस प्रकार निर्धारित की गई कि वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण हो सके और लंबे समय तक जल उपलब्ध रहे। पर्याप्त गहराई होने के कारण गर्मियों में भी जल का उपयोग संभव हो पा रहा है।

भुनेश देवांगन का घर बना सूर्यघर

रायपुर। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की ज़िंदगी रोशन कर रही है। यह योजना परंपरा गत ऊर्जा खपत को कम करने के साथ हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण को दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। कोंडागांव जिले के ग्रामीण अंचल के गांव शामपुर के रहने वाले श्री भुनेश देवांगन अब ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गए हैं।

श्री भुनेश देवांगन ने बताया कि इस योजना की जानकारी स्थानीय बिजली विभाग से मिली। योजना के बारे में विस्तार से समझने के बाद उन्होंने अपने घर की छत पर 5 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप पैनल लगवाया। सोलर प्लांट लगाने के 15 दिन बाद ही उन्हें केंद्र शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली 78 हजार की सब्सिडी प्राप्त हुआ।

5 किलोवाट की सोलर पैनल से केवल घर की बिजली खपत की आवश्यकता पूरी हो रही है, बल्कि अतिरिक्त बिजली का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने बताया कि पहले उन्हें हर महीने लगभग 3 हजार रुपये से साढ़े तीन हजार तक का बिजली बिल चुकाना पड़ता था, लेकिन अब उनका बिल शून्य हो गया है। साथ सोलर पैनल से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जा रही है, जिससे उन्हें भविष्य में अतिरिक्त आय भी मिलेगी। उन्होंने बताया पहले लो वोल्टेज की समस्या से बहुत परेशानी होती थी, अब उनकी यह चिंता दूर हुई है और महीने के बिजली बिल से भी छुटकारा मिला है।

महतारी वंदन योजना ने ग्राम मझगांव की सोहागा बाई को बनाया आत्मनिर्भर

■ **महिलाओं के जीवन में सरकार की योजनाओं से आई नई रोशनी**

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है। कबीरधाम जिले के ग्राम मझगांव की रहने वाली श्रीमती सोहागा बाई साहू आज आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी हैं।

कुछ वर्ष पहले तक संघर्षों से भरा उनका जीवन अब योजनाओं के संबल से खुशहाल बन गया है। खेती-बाड़ी और गृहस्थी की जिम्मेदारियों के साथ आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाली श्रीमती सोहागा बाई को महतारी वंदन योजना से हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है। इस सहयोग से वे घर-गृहस्थी के छोटे-मोटे खर्च आसानी से पूरा कर पा रही हैं।

श्रीमती सोहागा बाई बताती हैं कि यह योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अब उन्हें खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। साथ ही उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में भी स्वीकृत हो गया है, जिसके तहत जल्द ही उन्हें अपना पक्का घर मिलने वाला है।खेती-किसानी उनका प्रमुख सहारा है। थोड़ी सी जमीन पर मेहनत करके वे अनाज और सब्जियों की पैदावार से परिवार की जरूरतें पूरी करने के साथ अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित कर रही हैं। परिवार में बेटा और बहू भी सहयोग कर रहे हैं। खास बात यह है कि उनकी बहू को भी महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ हो गई है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। महतारी वंदन योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक संबल देकर आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रीमती सोहागा बाई जैसी सफलता की कहानियां इस योजना की वास्तविक उपलब्धि को दर्शाती हैं।

श्रीमती सोहागा बाई साहू ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी बदौलत आज ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और सम्मानपूर्वक जीवन जी पा रही हैं।

बिशुनपुर का अमृत सरोवर बना आजीविका गतिविधियों

■ **पहले से तीन गुना ज्यादा जलभराव में मछलीपान तथा 14 एकड़ में सिंचाई की सुविधा**

कोरिया। मानव निर्मित तालाब प्रकृति में जलसंरक्षण एवं भूमिगत जल संवर्धन की सबसे प्राचीन व्यवस्था है। इसे आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बीते वर्षों से मिशन अमृत सरोवर नामक अभियान चलाया गया है जिसका लाभ अब ग्रामीण क्षेत्रों में परिलक्षित होने लगा है। बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत के ग्राम बिशुनपुर में एक पुराना तालाब गाद जमने से अनुपयोगी हो गया था परंतु मिशन अमृत सरोवर के तहत उसके नवीनीकरण के बाद यह ग्राम पंचायत का एक बेहतरीन बहुपयोगी जल संसाधन बन गया है। आज इस अमृत सरोवर में पहले से तीन गुना ज्यादा जलभराव क्षमता हो चुकी है और अब आस पास के कई एकड़ खेतों में सिंचाई के लिए इस संसाधन का उपयोग हो रहा है। साथ ही यहां होने वाली मछलीपालन जैसी आजीविका गतिविधियों से महिलाओं के समूह को एक अतिरिक्त स्वरोजगार भी मिल रहा है।

अमृत सरोवरों की खासियत

ऐसे तालाब जिनका क्षेत्रफल एक एकड़ या उससे अधिक है और वह गाद जमने या अतिक्रमण का शिकार होकर अनुपयोगी हो चले हैं उन्हे इस अभियान के तहत चयनित किया गया है। उनका जीर्णोद्धार करते हुए कम से कम 10 हजार घनमीटर जलभराव क्षमता लायक बनाया गया और इन तालाबों में मछलीपालन जैसी आजीविका गतिविधियों को सुनिश्चित किया गया है। साथ ही जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यहां राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वजारोहण, स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, योग दिवस जैसी कई गतिविधियों को संपादित कराया जा रहा है।

धान के कटोरे से सुपर फूड की ओर : मखाना की खेती बनी महिलाओं के लिए समृद्धि का आधार

रायपुर। मखाने की आधुनिक खेती किसानों और महिला स्व-सहायता समूहों के लिए आय बढ़ाने का नया मार्ग है। यह पहल न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी है बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समाज को नई दिशा देने वाली है। प्रशासन का उद्देश्य है कि आने वाले वर्षों में मखाना खेती को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित कर किसानों को धान के बेहतर विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया जाए।

धमतरी में सुपर फूड मखाना, जिसे काला हीरा भी कहा जाता है,से अपनी पहचान बना रहा है। स्वास्थ्यवर्धक और पोषक तत्वों से भरपूर मखाने की खेती ने जिले के किसानों और महिला स्व-सहायता समूहों के जीवन में नई उम्मीदें जगा दी हैं। जिला प्रशासन ने इसे प्राथमिकता देते हुए धान की खेती के विकल्प के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है, ताकि किसानों की आमदनी दोगुनी हो सके और ग्रामीण आजीविका को मजबूती मिले।

कुरूद विकासखंड के ग्राम राखी, दरगहन और सरसोंपुरी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। इन गांवों के तालाबों में लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाने की खेती की जा रही है। राखी गांव में करीब 5 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल अब तैयार होकर हार्वेस्टिंग के चरण में पहुँच चुकी है। कटाई-छंटाई का यह कार्य प्रशिक्षित मजदूरों की मदद से किया जा रहा है क्योंकि मखाने की फसल में विशेष दक्षता की आवश्यकता होती है।

मखाना केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी अमूल्य वरदान है। इसमें विटामिन, कैल्शियम, मैग्निशियम, आयरन, जिंक और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह डायबिटीज और हृदय रोगियों के लिए उपयोगी है, हड्डियों और जोड़ों के दर्द में राहत देता है, रात को सेवन करने पर अच्छी नींद और तनाव मुक्ति प्रदान करता है तथा प्रोटीन और फास्फोरस से भरपूर होने के कारण शरीर को ऊर्जा और मजबूती देता है।

इस नई पहल ने गांवों में उत्साह का वातावरण बना दिया है। खासकर महिला स्वसहायता समूहों की भागीदारी उल्लेखनीय है। ग्राम देमार की शैलपुत्री महिला समूह और नई किरण महिला समूह ने मखाने की खेती और प्रसंस्करण का प्रशिक्षण लेकर इसे आजीविका का साधन बनाना शुरू कर दिया है। महिलाओं की यह भागीदारी न केवल उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही है बल्कि पूरे परिवार की जीवनशैली में सुधार लाने का माध्यम भी बन रही है। तकनीकी मार्गदर्शन के लिए कृषि विस्तार अधिकारी और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के विशेषज्ञ लगातार किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। तालाबों में केवल 2 से 3 फीट पानी में यह फसल आसानी से तैयार हो जाती है और लगभग छह महीने में कटाई योग्य हो जाती है। लाभ के लिहाज से भी मखाना धान से कहीं अधिक फायदेमंद साबित हो रहा है। धान की खेती में जहां औसत शुद्ध लाभ 32 हजार 698 रुपये आता है, वहीं मखाने की खेती से किसानों को लगभग 64 हजार रुपये तक की आमदनी हो रही है। यही कारण है कि जिला प्रशासन ने किसानों की बढ़ती रुचि को देखते हुए अगले रबी सीजन में 200 एकड़ तालाबों में मखाने की खेती विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है।

कारखाना भी चलने लगे अब सूर्यघर योजना की बिजली से

■ प्रधानमंत्री श्री मोदी की ड्रीम योजना हो रही बेहद लोकप्रिय

रायपुर। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आम जनता के बीच निरंतर लोकप्रिय हो रही है। इस योजना ने न केवल घरेलू उपभोक्ताओं को महंगे बिजली बिल से राहत दी है, बल्कि अब व्यावसायिक उपयोग के लिए भी लोग इसका लाभ उठाने लगे हैं। इससे उपभोक्ताओं को आत्मनिर्भरता के साथ-साथ दीर्घकालिक बचत भी सुनिश्चित हो रही है।

बिलासपुर स्थित कोनी निवासी श्री ओम अग्रवाल ने योजना के तहत अपने दोनों घरों की छत पर सोलर पैनल स्थापित किए हैं। पहले उन्होंने छह किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल घरेलू उपयोग के लिए लगवाया, जिसके लाभ को देखते हुए व्यावसायिक उपयोग हेतु अपने पुत्र मुरली अग्रवाल के नाम पर 10 किलोवाट का अतिरिक्त पैनल भी लगवाया। सौर ऊर्जा से अब उनके घर और व्यवसाय दोनों का बिजली बिल न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है।

श्री अग्रवाल ने बताया कि पूर्व में व्यवसाय में बिजली की अधिक खपत के कारण बिल काफी अधिक आता था, परंतु अब सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन होने पर यह समस्या समाप्त हो गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना दीर्घकालिक दृष्टि से अत्यंत किफायती एवं उपयोगी है। उनके पौत्र संस्कार अग्रवाल ने जानकारी दी कि दोनों सोलर पैनल स्थापित करने में लगभग नौ लाख रुपये की लागत आई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 2 लाख 16 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई। वर्तमान में दोनों घरों की छतों पर कुल 16 किलोवाट का सोलर पैनल संचालित हो रहा है, जिससे प्रतिमाह बिजली बिल में भारी कमी आई है।

परिवार का कहना है कि इस योजना में एक बार का निवेश कर 25 वर्षों तक निरंतर बिजली आपूर्ति प्राप्त की जा सकती है। साथ ही कंपनी द्वारा नियमित मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाकर बिजली के लिए आत्मनिर्भर बनें तथा पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को छतों पर रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

बलौदाबाजार जिले के किसान ऑयल पाम की खेती की ओर अग्रसर

रायपुर। भारत सरकार द्वारा तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल पाम संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में किसानों को ऑयल पाम की खेती हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप जिले के कृषकों में इस नई फसल को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। अब तक विकासखंड सिमगा के ग्राम जरौद में 2 हेक्टेयर एवं भाटापारा के ग्राम बिजराडीह में 6 हेक्टेयर, कुल 8 हेक्टेयर क्षेत्र में ऑयल पाम पौधों का रोपण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

ऑयल पाम खेती के फायदे

ऑयल पाम की खेती से प्रति एकड़ 10 से 12 टन वार्षिक उत्पादन प्राप्त होता है। इस खेती में न्यूनतम श्रम की आवश्यकता होती है तथा पौधों में रोग लगने की संभावना भी कम रहती है। इसके कारण दवाई पर होने वाला व्यय नगण्य रहता है। इस फसल की विशेषता यह भी है कि कृषकों को दलालों से मुक्ति मिलती है क्योंकि उपज का क्रय सीधे अनुबंधित कंपनियों द्वारा किया जाता है।

प्रारंभिक 4 वर्षों में प्रति हेक्टेयर लागत लगभग 25,000 से 30,000 रुपये आती है, जिसके अंतर्गत भूमि तैयारी, पौधरोपण, सिंचाई एवं खाद-उर्वरक सम्मिलित हैं। चौथे से छठे वर्ष तक प्रति हेक्टेयर 70,000 रुपये से 2,70,000 रुपये तक की अनुमानित आय प्राप्त होती है।

योजना के अंतर्गत कृषकों को सुविधाएँ

योजना के अंतर्गत कृषकों को प्रति हेक्टेयर 143 ऑयल पाम पौधों पर 29,000 रुपये की अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है। पौधों के रखरखाव, खाद-उर्वरक, थाला निर्माण आदि हेतु प्रथम वर्ष से चौथे वर्ष तक 5,250 रुपये प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर सहायता राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा 2,625 रुपये प्रति हेक्टेयर टॉप-अप सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। अंतरवर्ती फसल हेतु प्रथम से चौथे वर्ष तक अधिकतम 22,375 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। सिंचाई सुविधा हेतु न्यूनतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र में ऑयल पाम की खेती करने वाले कृषक को एक बोरवेल हेतु 50,000 रुपये तथा प्रति हेक्टेयर अधिकतम 25,000 रुपये प्रति यूनिट की अनुदान सहायता दी जाएगी। इसी प्रकार पम्पसेट हेतु 27,000 रुपये तथा प्रति हेक्टेयर 16,500 रुपये, फेंसिंग हेतु सीमेंट पोल एवं चौनलिंक पर 1,08,970 रुपये प्रति हेक्टेयर, तथा ड्रिप प्रतिस्थापन हेतु 14,130 रुपये प्रति हेक्टेयर के अतिरिक्त 8,635 रुपये टॉप-अप सहायता राशि प्रदान की जा रही है।

जशपुर जिले में 56 करोड़ 57 लाख की लागत से 484 नए आंगनबाड़ी भवन निर्माण की मिली स्वीकृति

जशपुरनगर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की प्राथमिकता हमेशा से प्रदेश के बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को लेकर रही है। इसी दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जशपुर जिले में 56 करोड़ से भी अधिक की लागत से 484 नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रत्येक आंगनबाड़ी भवन पर 11 लाख 69 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। इस प्रकार करोड़ों रुपए की राशि सीधे तौर पर जिले में आंगनबाड़ी सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और विस्तार पर लगाई जाएगी। इससे न केवल बच्चों और माताओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी बल्कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी एक स्थायी और सुसज्जित कार्यस्थल प्राप्त होगा।

जर्जर भवन एवं अस्थाई से स्थायी भवन की ओर : अब तक अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र भवन जर्जर हालत में या किराए के मकानों में संचालित होते थे।ऐसे स्थानों में न तो बच्चों को बैठने की समुचित सुविधा मिलती थी और न ही साफ-सफाई का पर्याप्त वातावरण। लेकिन नए भवन बनने के बाद बच्चों को स्वच्छ, सुरक्षित और अनुकूल माहौल उपलब्ध होगा, जिससे उनकी शिक्षा और पोषण संबंधी गतिविधियाँ व्यवस्थित ढंग से संचालित होंगी।

बच्चों और माताओं के लिए एक संपूर्ण केंद्र: नए आंगनबाड़ी भवन सिर्फ पढ़ाई या आहार वितरण का स्थान नहीं होंगे, बल्कि ये ग्रामीण समाज में पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता का केंद्र बनेंगे।

इन भवनों में बच्चों को पौष्टिक आहार ,खेल-खेल में सीखने की व्यवस्था,नियमित स्वास्थ्य जांच,माताओं के लिए पोषण व स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी। इससे जिले में कुपोषण को कम करने और शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने में बड़ी भूमिका निभाई जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का संकल्प अब कोई भी बच्चा शिक्षा की कमी से नहीं होगा वंचित: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा का संकल्प है कि जशपुर का कोई भी बच्चा अब कुपोषण और शिक्षा की कमी से वंचित नहीं रहेगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चे और हर माता को स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। नए आंगनबाड़ी भवन आने वाली पीढ़ी के जीवन स्तर को बेहतर बनाएंगे और प्रदेश में पोषण क्रांति की नींव मजबूत करेंगे।

ग्रामीणों की खुशी और सीएम साय के प्रति आभार: ग्रामीण अंचलों के लोगों ने इस नए आंगनबाड़ी भवन की स्वीकृति का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि यह पहल आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्ज्वल बनाने वाली साबित होगी। अब बच्चे अस्थायी कमरों में नहीं, बल्कि सुसज्जित भवनों में शिक्षा और पोषण प्राप्त करेंगे।

सहकारिता के माध्यम से किसानों के जीवन में आ रही खुशहाली : डॉ. रमन

- चारों जिले के सहकारी बैंकों से 5 लाख 40 हजार किसान सहकारिता से हो रहे लाभान्वित
- कृषक उन्नति योजना के तहत 4559 करोड़ 66 लाख रूपए की राशि किसानों के बैंक खाते में की गई अंतरिती

राजनांदगांव। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम राजनांदगांव में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव द्वारा आयोजित सहकारी सम्मेलन में शिरकत की।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव, कबीरधाम, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान -गण्डई जिले से बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं कृषक यहां सहकारी सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे है। उन्होंने कहा कि सहकारिता में बहुत ताकत है। सहकारिता के माध्यम से किसानों के जीवन में खुशहाली एवं परिवर्तन आ रहे है। छत्तीसगढ़ में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया गया, जिससे उनके जीवन में खुशहाली आयी। किसानों का जीवन पहले अधिया की भरपायी करते हुए निकल जाता था और साहुकारों के चंगुल में फंसकर ब्याज देते-देते परेशान हो जाते थे। सहकारिता एक चमत्कार है और केंद्रीय सहकारिता बैंक से चारों जिले के 5 लाख 40 हजार किसान सहकारिता से लाभान्वित हो रहे हैं। उनके जीवन में सहकारिता से जुड़ने पर महत्वपूर्ण परिवर्तन आए है। कृषक उन्नति योजना के तहत धान खरीदी अंतर्गत रिकार्ड तोड़ धान खरीदी की गई है और लगभग 4559 करोड़ 66 लाख रूपए की राशि कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में अंतरित की गई है। जिले में बैंकिंग सुविधाओं में बढ़ोत्तरी हुई है। एटीएम एवं माईक्रो एटीएम की सुविधा किसानों को मिल रही है। माईक्रो एटीएम के तहत पहले किसान 10 हजार रूपए निकाल सकते थे, अब इसकी क्षमता बढ़ाकर 20 हजार रूपए कर दिया गया है। इसी तरह रूपे डेबिट कार्ड से 20 हजार रूपए से क्षमता बढ़ा दी गई अब 40 हजार रूपए तक की राशि आहरण कर सकते है।

किसानों के आय में हुई वृद्धि : संतोष पांडे- सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने कहा कि केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में बैंकिंग सुविधाओं में वृद्धि हुई है। एटीएम की सुविधा बढ़ी तथा कम्प्यूटरीकरण से कार्यों में तेजी आयी है। किसानों की आय में वृद्धि हुई, बैंक खाते खुले तथा बचत एवं सहभागिता की प्रवृत्ति बढ़ी। सब मिलकर एवं संगठित होकर एक साथ कोई बड़ा कार्य करते है, तो वह सफल होता है। उन्होंने किसानों की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

किसान देश का सम्मान और किसानों से हो रही है देश की उत्तरोत्तर प्रगति : कश्यप

वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, सहकारिता, संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि देश के विकास के लिए जय जवान-जय किसान का अह्वान किया गया। किसान देश का सम्मान है और किसानों से देश की उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है और सभी सहकारिता से जुड़े है। सहकारिता का यह आंदोलन जन-जन तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप हमारा देश विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2058 पैक्स है और कॉमन सर्विस सेंटर में सुविधाएं दी जा रही है। 532 नये पैक्स का गठन किया गया है। जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। सभी ग्राम पंचायतों में सहकारी समिति होनी चाहिए, ताकि किसानों को लाभ मिल सके।

सचिन बघेल ने किया प्रतिवेदन का वाचन

अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित श्री सचिन बघेल ने प्रतिवेदन का वाचन किया। उन्होंने बताया कि बैंक की अंशपूंजी 31 मार्च 2024 पर 19244.60 लाख रूपए थी, जो 31 मार्च 2025 में बढ़कर 20557.82 लाख रूपए हो गई है अर्थात अंशपूंजी में 1313.22 लाख रूपए की वृद्धि हुई है। निधियों में 5636.66 लाख रूपए की वृद्धि हुई है। 31 मार्च 2025 पर बैंक का शुद्ध लाभ 2123.56 लाख रूपए एवं संचित लाभ 5830.43 लाख रूपए है। 31 मार्च 2025 पर बैंक का एनपीए 4244.25 लाख रूपए है, जो कुल ऋण का 6.24 प्रतिशत है। बैंक द्वारा वर्ष 2024-25 में कृषकों को 160529.88 लाख रूपए का ऋण वितरण किया गया है। बैंक के कार्यक्षेत्र में कुल 275 खाद केन्द्र संचालित है। जिसके माध्यम से कृषकों को खाद उठाव करने में सुविधा प्राप्त हो रही है।

इनकी रही मौजूदगी

इस अवसर पर विधायक पंडरिया श्रीमती भावना बोहरा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक श्री केदार नाथ गुप्ता, राजनांदगांव जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नम्रता सिंह, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री विक्रांत सिंह, पूर्व विधायक श्री विनोद खांडेकर, पूर्व विधायक श्री कोमल जंघेल, पूर्व विधायक श्री मोतीलाल चंद्रवंशी, पूर्व विधायक श्री रामजी भारती, श्री कोमल सिंह राजपूत, श्री प्रदीप गांधी, श्री रमेश पटेल, श्री दिनेश गांधी, श्री राजेंद्र चंद्रवंशी, श्री खूबचंद पारख, श्री संतोष अग्रवाल, श्री सुरेश एच लाल, श्री राजेन्द्र गोलछा सहित राजनांदगांव, कबीरधाम, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले के जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में कृषकगण उपस्थित थे।

किसानों को 6636 करोड़ रुपए का मिला ब्याज मुक्त ऋण

चालू खरीफसीजन में प्रदेश के 14.96 लाख किसान हुए लाभान्वित

- सभी 2058 पैक्स सोसायटियो में पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित
- किसानों को डेयरी, मत्स्य पालन और वनोपज प्रसंस्करण से जोड़ने पर दें विशेष ध्यान: श्री गुप्ता

रायपुर। छत्तीसगढ़ में चालू खरीफसीजन में किसानों को 6636 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जा चुका है। ब्याज मुक्त ऋण वितरण से 14 लाख 96 हजार किसान लाभान्वित हुए है। यह जानकारी अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी श्री केदार नाथ गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई।

अपेक्स बैंक की बोर्ड की बैठक में श्री केदार नाथ गुप्ता ने कहा कि डेयरी, मत्स्य पालन और वनोपज प्रसंस्करण जैसी रोजगार आधारित योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने खाद की उपलब्धता और वितरण की समीक्षा करते हुए कहा सहकारिता के अंतर्गत कि इस साल खरीफ सीजन के लिए राज्य सरकार ने 10.72 लाख मेट्रिक टन खाद वितरण का लक्ष्य रखा है, और अब तक 8 लाख 69 हजार मेट्रिक टन खाद का भंडारण किया गया है। इनमें से 8 लाख 01 हजार मीट्रिक टन खाद किसानों को वितरित किया जा चुका है। समितियों के गोदामों में 67 हजार मेट्रिक टन खाद उपलब्धता है।

पैक्स सोसायटियों में 2058 माइक्रो एटीएम स्थापित

बैठक में यह भी बताया गया कि, राज्य के सहकारी बैंकों में 262 एटीएम और सभी पैक्स सोसायटियों में 2058 माइक्रो एटीएम स्थापित किए गए हैं। साथ ही किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी 2058 पैक्स सोसायटियो को पीएम किसान समृद्धि केंद्र बनाए गए। इससे किसानों को आसानी से अपने खाते से राशि निकालने की सुविधा मिल रही है। बैठक में नाबार्ड के उप महाप्रबंधक श्री अजय थुटे, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री के.एन. कांडे, संयुक्त पंजीयक श्री उमेश तिवारी, उप पंजीयक व महाप्रबंधक श्री युगल किशोर, ओएसडी श्री अविनाश श्रीवास्तव, एजीएम श्री अरुण पुरोहित, एजीएम श्री एल के चौधरी और अन्य बैंक के अधिकारी उपस्थित थे।

ग्राम सकरी में 49.9 लाख के विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण

- राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा बोले- तेजी से विकास कार्य कराएं जा रहे हैं

रायपुर। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने रविवार को बलौदाबाजार प्रवास के दौरान ग्राम पंचायत सकरी में 49.9 लाख रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया।

मंत्री श्री वर्मा ने जिन विकास कार्यों का लोकार्पण- भूमिपूजन किया उनमें 16 लाख रुपए से किसान कल्याण उत्पादक सहकारी समिति कार्यालय का भूमिपूजन शामिल है। इसी प्रकार 5 लाख रुपए से गली कांक्रीटीकरण, 3 लाख रुपए से महामाया मंदिर परिसर में रंगमंच निर्माण, 6.9 लाख रुपए की लागत से योगा शेड का निर्माण, 16 लाख रुपए से महतारी सदन और 3 लाख रुपए से बाजार चौक में रंगमंच भवन का लोकार्पण शामिल है।

हमारी सरकार गांव गरीब, किसान, जवानों के लिए कर रही काम : वर्मा- इस अवसर पर मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि हमारी सरकार गांव गरीब, किसान, जवानों के लिए विकास कार्यों को गति दे रही है। जनता से किए गए वादों को समय में पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के जनहितैषी निर्णयों से प्रदेश में खुशहाली का माहौल है। महतारी सदन का उपयोग महिला समूहों की बैठकों और सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा।

इनकी भी रही मौजूदगी

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, जनपद अध्यक्ष सुलोचना यादव, भारत स्काउट गाइड के राज्य उपाध्यक्ष विजय केशरवानी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

स्वामी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा प्रकाशक एवं मुद्रक छग राज्य सहकारी संघ रायपुर द्वारा मयंक ऑफसेट रायपुर से मुद्रित कराकर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित 16, पार्क स्ट्रीट-3, चौबे कालोनी रायपुर से प्रकाशित।
संपादक मंडल- विवेकानंद झा (प्रधान संपादक), विवेक पांडे (संपादक), फोन- 0771-4061702, 4031702, 4035702. वेबसाईट www.cgcoop.in E-mail: cgcoopnews@gmail.com